

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मेट्रिक के बाद अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ

4738. श्री गं० च० दीक्षित : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश में 1966-67 में मेट्रिक-कुलेशन के बाद अध्ययन के लिये कितनी छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है;

(ख) इस अवधि में मध्य प्रदेश में छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं, और

(घ) यदि हाँ, तो कितने विद्यार्थियों को और कब कब छात्रवृत्तियाँ दी गईं,

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कूलरेषु गृह) : (क) इस योजना के अर्धीन छात्रवृत्तियों की संख्या नियत नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सभी पात्र छात्रवृत्तियों के लिये पात्र हैं।

(ख) (1) अनुसूचित जातियाँ 4,324

(2) अनुसूचित आदिम जातियाँ 1,587

5,911

(घ) और (घ) वर्ष 1966-67 में अनुसूचित जातियों के 3,798 छात्रों को तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 1,445 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं। जिले-जिले में तथा सस्था-सस्था में तारीखों की विवृता है।

Financial Aid to Eastern Districts of U.P.

4739. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Raj Deo Singh:
Shri Shambhu Nath.

Will the Minister of Finance be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Central aid has been discontinued since 1965-67 and the Government of U.K. has been asked by the Central Government to implement the Patel Commission's recommendations to the Districts of Deoria, Azamgarh, Ghazipur and Jaunpur,

(b) if so, the extent to which the U.P. Government has implemented the said scheme,

(c) whether the Central Government are aware that this scheme has been abandoned by the Uttar Pradesh Government, and

(d) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai). (a) In 1965-66, additional assistance of Rs 45, crores was provided to the Government of U.P. for the implementation of the special programme of development of Eastern Districts, from 1966-67 onwards, the programmes are being implemented as a part of the State Plan and assisted by the overall total assistance for the State Plan

(b) the implementation of the recommendations commenced in 1964-65. A total additional outlay of Rs 810 crores was incurred during 1964-65 and 1965-66. The estimated outlay on the development of these districts in 1966-67 is Rs 1152 crores.

(c) and (d) The scheme has not been abandoned by the State Government.